और संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के प्रतिनिधियों के रूप में नामित किया गया हैं। दोनों पक्षों की ओर से अधिकारियों के सुगाठित दल ने दोनों नेताओं की सहायता की थी।

यह बताचीत पूर्णाधिवेशनों और नामित अधिकारियों के छोटे-छोटे समूहों में मीन दिन से अधिक तक चली। इसके अतिरिक्त श्री स्ट्रोव तालबोट ने प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री और कुछ राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात भी की।

बातचीत उन व्यापक प्रस्तावों के आधार पर चलाई जा रही हैं जिन्हे भारत ने निरस्त्रीकरण तथा शस्त्र अप्रसार मामलों, यथा-विस्फोट नाभिकीय परीक्षणों पर एक पक्षीय छूट, इसे विधितः दायित्व में बदलने पर बातचीत करने की इच्छा, एफ एम सी टी पर रचनात्मक बातचीत में सम्मिलित होने के निर्णय और संवदेनशील प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर कड़े नियंत्रण- पर हमारी नीतियों की पुनः पुष्टि करने पर प्रस्तुत किया था।

अमरीका के साथ बातचीत के कई दौर के बाद बातचीत का दायरा संकुचित हुआ हैं और अब यह सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और शस्त्र अप्रसार यथा-नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंध संधि, भारतीय सुरक्षात्मक स्थिति और निर्यात नियंत्रण मुद्दे से जुड़ चार मुद्दों पर केन्द्रित है।

दोनों देशों के शिष्टमंडलों ने बातचीत के निष्कर्ष पर सन्तोष व्यक्त किया। पिछली बातचीत की तरह दोनों पक्षों के सुरक्षा संबंधी पर परिप्रेक्ष्यों को और स्पष्ट किया गया ताकि अपने-अपने परिप्रेक्ष्यों में मेल-मिलाप की स्थिति बनाई जा सके।

यह निर्णय किया गया हैं कि निर्यात नियंत्रण पर अनुवर्ती बातचीत के लिए भारत-अमरीकी विशेषज्ञ स्तर के दलों की मार्च में एक बैठक होगी। शिष्टमंडलों के नेता भी परस्पर सम्पर्क में रहेंगे। इन बातचीतों के चलते दोनों पक्ष अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए रचनात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे।

(ख) और (ग) बातचीत सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और अप्रसार से संबंधित मुद्दों पर केन्द्रित है। इस बात पर सहमति हुई कि क्षेत्रीय मसलों को साथ-साथ अलग से रखा जाएगा। तथापि, अफगानिस्तान सहित अन्य अलग-अलग चर्चाओं के लिए दोनों पक्षों के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति का लाभ उठाया जाता हैं।

अमरीका ने यह बताया हैं कि उसका यह विचार हैं कि अफगानिस्तान में सैन्य समाधान सम्भव नहीं हैं। और वह अफगानिस्तान में व्यापक आधारित सरकार की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान के अन्तर्गत आपसी बातचीत से हुए समझौते के पक्ष में हैं।

"सयुक्त राष्ट्र संघ की छः योग दो प्रक्रिया (सिक्स प्लस टू प्रोसेस)

378. **डा. महेश चन्द्र शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ की "छः योग की दो प्रक्रिया" (सिक्स प्लस टू प्रोसेस) क्या हैं; और

(ख) यह भारतीय प्रायद्वीप से किस प्रकार जुड़ा हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) "सिक्स प्लस टू प्रोसेस" से अभिप्राय अनौपचारिक परामर्श की उस प्रकिया से हैं जिसके अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र के कुछ सदस्य राज्य अफगानिस्तान के मसले पर एक-दूसरे से परामर्श करते हैं। इयमें ईरान, पाकिस्तान, उजबेकिस्तान, ताजिस्तिन, तुर्कमेनिस्तान, चीन रूसी परिस्संघ तथा अमरीका शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में इस दल की कोई औपचारिक उपस्थिति नहीं हैं। यह अनौपचारिक दल भारतीय प्रायद्वीप से सीधे तौर पर संबद्व नहीं हैं।

जम्मू और कश्मीर का पाकिस्तानी मानचित्र में गलत तरीके से दर्शाया जाना

379. **श्री डी.पी. यादव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से को अपने मानचित्र में दर्शा रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में अपनी आपत्ति दर्ज कराई हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) से (ग) पाकिस्तान अपने मानचित्र में जम्मू और कश्मीर के भारतीय राज्य की स्थिति को सही नहीं दर्शाता हैं। इस मुद्दे पर सरकार के विचारों की पाकिस्तान को पूरी जानकारी हैं।